लेह में भारी हिंसा, भाजपा कार्यालय को आग लगाई, चार की मौत, कई घायल

- लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन के हिंसक रुप लेने के खिलाफ विख्यात एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 15 दिन की भूख हड़ताल वापस ले ली।
- हिंसा तब भड़की जब सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल कर रहे दो लोगों की तबियत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

लेह, 24 सितंबर। लद्दाख़ को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार, भाजपा दफ्तर में आगजनी की गई। हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में धारा 163 लागू कर दी गई है। एक साथ पांच या उससे ज़्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। बिना इजाज़त के जुलूस या प्रदर्शन पर भी पाबंदी है।

वहीं, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह शहर में हुई हिंसक घटना की कड़ी निंदा की है, उपराज्यपाल ने दुखद मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।

एक अधिकारी ने बताया कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की और भाजपा कार्यालय और कई वाहनों पर हमला किया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी।

हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का अनशन तोड़ दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण रास्ते का प्रयास विफल हुआ है।

लद्दाख की हालात को स्थिर करने के लिए सीआरपीएफ की चार कंपनियों (कुल मिलाकर 4 सौ जवान मौजूद हैं) को कश्मीर से लद्दाख भेजा गया। इससे पहले सीआरपीएफ की सात कंपनियां लद्दाख में पहले से ही तैनात है जिसमें कुल मिलाकर 700 जवान हैं।

हिंसक प्रदर्शन के बाद बुधवार को प्रशासन ने लद्दाख के लेह जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने निषेधाज्ञा आदेश जारी कर कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन होने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

भारतीय आईटी प्रोफैशनल्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आकर्षक है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो यूरोप जाने को तैयार हैं। जर्मनी के नए "ऑपर्च्युनिटी/चांसनकार्टे" कदमों का उद्देश्य कुशल पेशेवरों को, तत्काल एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के बिना भी अवसर देना है। जो तकनीकी प्रतिभाएं सामाजिक सुरक्षा, रिसर्च लिंक और यूरोपीय बाज़ारों की निकटता को महत्व देती हैं, उनके लिए जर्मनी (और पूरा यूरोपीय संघ) भरोसेमंद विकल्प है, हालाँकि गैर-अंग्रेज़ी वर्कप्लेस और कागज़ी प्रक्रिया कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं।

ब्रेक्ज़िट के बाद ब्रिटेन ने ग्लोबल टैलेंट रूट जैसे वीज़ा और विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर नियमों में ढील देकर प्रतिभाओं को लुभाने की कोशिश की है। लंदन के वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। लेकिन स्किल्ड वर्कर लिस्ट और वेतन सीमा में हाल के बदलावों से अनिश्चितता बढ़ी है। इसलिए ब्रिटेन वरिष्ठ विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए तो आकर्षक है, पर बड़े पैमाने पर जूनियर आईटी स्टाफ़ के देश में आने के लिए उतना भरोसेमंद नहीं।

सिंगापुर ने ओवरसीज़ नेटवर्क्स एंड एक्सपर्टीज़ पास (वन पास) जैसे प्रीमियम वीज़ा शुरू किए हैं जो ऐसे वरिष्ठ नेताओं, संस्थापकों और ऊँची आय वालों के लिए आदर्श हैं, जो एक संक्षिप्त, व्यवसाय अनुकूल शहर-राज्य और फास्ट रैज़िडैंसी बैनिफिट (लाभ) पसंद करते हैं। यूएई की गोल्डन/ग्रीन वीज़ा निवेशक स्कीम, निवेशकों, उच्च आय वाले पेशेवरों और विशेष प्रतिभाओं को लंबे समय की रैज़िडैंसी देती है। यह उन लोगों के लिए आकर्षक है जो टैक्स की सुविधा, ऊँचे वेतन और भारत के नज़दीक रहने को प्राथमिकता देते हैं। ये वीज़ा शुरुआती इंजीनियरों के लिए कम उपयोगी हैं लेकिन वरिष्ठ प्रतिभा और उद्यमियों के लिए बहुत आकर्षक हैं। बड़ी टेक कंपनियाँ और धनवान बहुराष्ट्रीय निगम अब भी अमेरिका में प्रतिस्पर्धा कर पाएँगे क्योंकि वे ऊँचे वेतन स्तर की मांग पूरी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सबसे कम नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा असर जूनियर पेशेवरों, छोटे-मझोले उद्यमों और स्टार्टअप्स पर पड़ेगा जो कम वेतन पर वैश्विक भर्ती करते हैं। कैनडा, यूरोप के कुछ हिस्से और खाड़ी देश शुरुआती से मिड-करियर भारतीयों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करेंगे, जबकि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया मिड से सीनियर प्रतिभा को अपनी तरफ खींचेंगे।

अगर दूसरे देश आसान या त्वरित रैज़िडैंसी की पेशकश करते हैं तो भारत से युवा कोडरों और मिड-करियर विशेषज्ञों का पलायन हो सकता है। एच-1 बी पर निर्भर एम्प्लॉयरों को या तो वेतन में बड़ा इज़ाफ़ा करना होगा, भर्ती रणनीतियाँ बदलनी होंगी (जैसे अमेरिका में स्थानीय टीम बनाना) या भर्ती के भौगोलिक विकल्प बढ़ाने होंगे। उम्मीदवारों के लिए अब वेतन और दीर्घकालिक सुरक्षा के बीच संतुलन महत्वपूर्ण होगा: कैनडा और ऑस्ट्रेलिया स्थायी निवास का साफ रास्ता देते हैं, यूरोप जीवनशैली और सामाजिक लाभ देता है, जबकि सिंगापुर और यूएई ऊँची आय और भारत की नज़दीकी का फायदा देते हैं।

'बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार लाने में आठ साल लग गए, और अब सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि हर आर्थिक सुधार पर भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए जो रुख अपनाया, सत्ता में आने पर उसका उल्टा रुख लिया। पायलट ने कहा कि बिहार में हाल ही में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और राज्य में बदलाव का स्पष्ट माहौल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की सभी पार्टियाँ एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ रही हैं। पायलट ने कहा, अमेरिका भारत पर आर्थिक हमला कर रहा है और हम उसका जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं।"

उन्होंने यह भी जोड़ा कि पीएम मोदी और ट्रंप की मित्रता देश के लिए बहुत भारी पड़ रही है। सचिन पायलट ने जाति जनगणना पर कहा कि सरकार को जातिगत जनगणना को महज औपचारिकता न बनाकर उसे इस तरह कराना चाहिए जिससे वास्तविक सामाजिक भागीदारी का चित्र सामने आए। सिर्फ जनगणना के कॉलम में जाति जोड़ने से काम नहीं चलेगा। पायलटन ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए "वोट चोरी" के मुद्दों पर जाँच शुरु करने के बजाय आयोग उनसे शपथ पत्र माँग रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया, जब सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं, तो जवाब भाजपा की तरफ से आता है। उन्होंने दोहराया कि बिहार चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब पायलट से पूछा गया कि कांग्रेस अभी तक राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा, सभी निर्णय सही समय पर लिए जाएंगे।

मल्लिकार्जुन खड़गे दो साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दी जाती है, न कि पूर्णकालिक महासचिव की। एक बार सीडब्ल्युसी में शामिल होने के बाद वे आधिकारिक महासचिव के रूप में कार्य कर सकते हैं। एके एंटनी और अंबिका सोनी को हटाने की कोशिश मुख्यत: उम्र कारक से प्रेरित मानी जा रही है। एंटनी (84 वर्ष) 2022 से ही राजनीति से दूर हैं, जबकि 82 वर्षीय अंबिका सोनी अब भी सक्रिय हैं। एंटनी को अपने बेटे अनिल के भाजपा में शामिल होने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अंबिका सोनी का प्रभाव सोनिया गांधी की कृपा से लंबे समय तक रहा है। उनके दौर (1998-2022) में कई नेता उन्हें 'सोनिया माइनस ए' कहा करते थे। उनके कई समर्थक भी थे जैसे कमलनाथ, सलमान खुर्शीद, कुमारी शैलजा और पवन बंसल आदि।

चुनावी राज्य बिहार कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है, जहाँ राहुल गांधी ने 1300 किलोमीटर लंबी 'वोट अधिकार यात्रा' निकाली। इस यात्रा में तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव जैसे महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने बड़ी भीड़ खींची और अच्छी भाषण शैली से अपने विरोधियों को भी प्रभावित किया।

हालांकि, कांग्रेस के आंतरिक मूल्यांकन से पता चलता है कि यह यात्रा वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगी। कांग्रेस के सूत्र मानते हैं कि यह अभियान दिखावे में तो जोरदार था, लेकिन मुद्दों पर कमजोर रहा। वोटिंग अधिकार का मुद्दा भी विरोधाभासी रहा - जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वे संतुष्ट हैं, और जिनका नाम गायब है, वे वोट नहीं डाल पाएंगे, इसलिए चुनाव में उनका असर सीमित रहेगा। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर और असंगठित है, जिससे प्रभावी जनसंपर्क मुश्किल है। इसके अलावा, कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न करने से और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। तेजस्वी मानते हैं कि वे महागठबंधन के स्वाभाविक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार, उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी 'वोट अधिकार यात्रा' के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से सीएम उम्मीदवार घोषित करेंगे।

केरल में भी कलह बड़ी समस्या है। यहां 'वोट वाइब' एजेंसी के अनुसार, शशि थरूर पिनराई विजयन के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं। थरूर की लोकप्रियता 28.4 प्रतिशत है, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस नेता काफी पीछे हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 4.2 प्रतिशत, वी.डी. सतीशन 15 प्रतिशत, सनी जोसेफ 2 प्रतिशत, रमेश चेन्निथला 8.2 प्रतिशत, और के मुरलीधरन 6 प्रतिशत पर हैं।

17 फरवरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकते हैं। परीक्षा देश के अलावा अन्य 26 अन्य देशों में भी आयोजित की जायेगी। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हर विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू होगा और इसके 12 दिनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, अगर 12वीं की भौतिकी की परीक्षा 20 फरवरी 2026 को होगी तो मूल्यांकन 3 मार्च से शुरू होगा और 15 मार्च तक चलेगा।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सामने आया कि तीनों आरोपियों ने पेपर लीक माफिया के जरिए परीक्षा से पहले सॉल्वड पेपर हासिल किया था। फिर उसे पढ़कर लिखित परीक्षा पास की। परमेश चौधरी ने मेरिट में 180 वीं,, मनोहर सिंह जाट ने 38वीं और मनोहर लाल विश्नोई ने 171वीं रैंक हासिल कर एसआई भर्ती में नियुक्ति हासिल की।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पढ़कर वे लिखित परीक्षा में ना सिर्फ उत्तीर्ण हुए, बल्कि इंटरव्यू में भी आर.पी.एस.सी. सदस्यों की मिलीभगत से अच्छे अंक ला पाए।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस मामले की जांच में हर सप्ताह पेपरलीक के आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या अब तक 77 हो चुकी है। आज सुनवाई के दौरान भी 3 ट्रेनी एस.आई. पकड़े गए हैं। ऐसे में अगर एस.आई. भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए तो इससे आमजन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि, राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिन रिपोर्ट्स के आधार पर एस.आई. भर्ती को रद्द करने योग्य माना था, खंडपीठ ने उन रिपोर्ट्स को अप्रमाणित माना है।

इसके जवाब में राज्य सरकार के ए.ए.जी. शिवमंगल शर्मा ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए, लेकिन उनकी फील्ड ट्रेनिंग को जारी रखा जा सकता है।

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट की खंडपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। वहीं हाईकोर्ट को तीन महीने में अपील का निस्तारण करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद वर्तमान में एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक हटी है, ऐसे में राज्यसरकार के पास भी विकल्प बचता है कि वह चाहे तो एसआई भर्ती-2021 को रद्द करते हुए आर.पी.एस.सी. से पुन: पुरानी विज्ञिप्ति के अनुसार इन्हीं पदों पर दुबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के 28 अगस्त वाले भर्ती रद्द करने के फैसले पर 8 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही एस.आई. भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग देने पर पूर्व में लगी हुई रोक को बरकरार रखा था। ज्ञात रहे कि इस मामले में एकलपीठ ने 28 अगस्त को दिए फैसले में माना था कि एसआई भर्ती रद्द करना सही होगा। इसके अलावा भर्ती रद्द करने के लिए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आरपीएससी में देने को कहा था।

प्रधानमंत्री आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लागत वाली माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह संयंत्र बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील के गांवों में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 63,683 करोड़ रुपए की स्वच्छ ऊर्जा एवं ट्रांसमिशन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री 491 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में 220 केवी के 4 जीएसएस का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें ईसरदा से जयपुर, भरतपुर और अलवर जिलों तक फीडर निर्माण, बीसलपुर और ब्राह्मणी बैराज जैसे महत्वपूर्ण जल प्रोजेक्ट शामिल हैं।

प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री 2636 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क और पुल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के 11 जिलों में 5884 करोड़ की लागत से पेयजल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। भरतपुर में 128 करोड़ की लागत से 250 बेड के अस्पताल, जयपुर में 140 करोड़ की लागत से आईटी डवलपमेंट सेंटर, और मकराना व मंडावा में 226 करोड़ की सीवरेज व जलप्रदाय परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत और उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र देंगे। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। यह दौरा राजस्थान के विकास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

राज्यसभा की 5 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर तक की जायेगी और उम्मीदवार द्वारा 16 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

आयोग ने बताया कि राज्य सभा की द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया के तहत 24 अक्टूबर को इन सभी पांच सीटों के लिए सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम पांच बजे से वोटों की गिनती का काम शुरु कर दिया जाएगा।

रेल कर्मचारियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए मंत्रिमंडल ने 10,91,146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पात्र रेल कर्मचारियों को उत्पादकता-आधारित बोनस का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा या दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600